

MR. CHAIRMAN : Now, all the names in the list is exhausted. There are three more notices received after 9.30 a.m. For the time being, I shall call those names.

DR. K.S. MANOJ (ALLEPPEY): Sir, NACO has given green signal to install Condom Vending Machines in our university campuses. Delhi State AIDS Control Society has installed Condom Vending Machines in JNU and Delhi University Campuses. By "the overwhelming response", as stated by the Chairperson of the Delhi State AIDS Control Society to the venture, the NACO has decided to install this machine in the other campuses also.

Sir, the installation of Condom Vending Machines in the campuses give a false message to the students and will promote free sex in the campus and will add more to the menace of HIV/AIDS.

Sir, Condom is not 100 per cent safe against HIV/AIDS and also gives a false sense of security. This move is actually an insult to our nation's culture and heritage. So, I urge upon the Government to revoke the move to install Condom Vending Machines in the campuses and prevent cultural decline of our universities.

**चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) :** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अहम विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरे हिन्दुस्तान में, खासकर जम्मू-कश्मीर और पंजाब में, जैसा आप जानते हैं कि जब आतंकवाद शुरू हुआ था, तो भारत सरकार ने उसका मुकाबला करने के लिए होमगार्ड बनाया था। उन्हें महीने में सिर्फ 13 दिन ड्यूटी देनी थी और 13 दिन की ही उन्हें तनख्वाह मिलती थी। जब जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी भड़कनी शुरू हुई, तो भारत सरकार की तरफ से एसपीओ और वीडिसी को लगाने का आर्डर दिया गया। उसका खर्चा केन्द्र सरकार ने वहन करने की बात कही थी। उसके लिए जो विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई गईं, वे मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सामने आईं।

हजारों लोग उनमें भर्ती हुए, जिसमें कई लोग मारे गए, शहीद हुए और आज भी हो रहे हैं। उन्होंने पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में मिलिटेंसी को कर्ब किया, जहां कोई जा नहीं सकता था।

MR. CHAIRMAN: You please mention as to what is your demand.

**चौधरी लाल सिंह** : आप मेरी डिमांड पढ़ लें, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। एसपीओ और वीडिसी जो गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए, आज उनकी तनख्वाहें और वर्दी उन्हें नहीं मिल रही हैं। तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है। जब उनकी कैजुअलटी हो जाती है, क्योंकि वे कांस्टेबल नहीं हैं, इसलिए उनके आश्रितों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। उस समय भर्ती के वक्त उनकी आयु 20 साल थी। आज 15 साल हो गए हैं, इसलिए उनकी उम्र अब 35 साल हो गई है। उनमें से कुछ चले गए और कुछ जिन्दा हैं। लेकिन आज वे लोग पुलिस में नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरएज हो गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह मसला बहुत गम्भीर है, जम्मू-कश्मीर के इन बच्चों को केन्द्र सरकार की तरफ से जो कम्पनीज वहां बनानी हैं, उनमें नौकरी दी जाए। वे लोग ओवरएज हो गए हैं और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनके घर तक अनसेफ हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि उन्हें इन सुरक्षा बलों में रिक्रूट किया जाए।

**श्री मुंशी राम (बिजनौर)** : सभापति जी, मेरा लोक सभा क्षेत्र, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भाग है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय देश में चीनी उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, परन्तु बड़े दुख के साथ इस सदन को अवगत कराना पड़ रहा है कि इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादन करने वाले करोड़ों किसानों को